सत्यमेव जयते

सिक्किम विधानसभा के

बजट सत्र में

माननीय राज्यपाल

श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का

संबोधन

दिनांक - 17 मई, 2023

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के गणमान्य सदस्यगण।

राज्यपाल के रूप में बजट सत्र 2023-24 का अभिभाषण प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और पहलों पर प्रकाश डाला गया है। राज्य का बजट एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय नियोजन है, जो सरकार को अपने वित्त का प्रबंधन करने, नीतियों को लागू करने, संसाधनों को आवंटित करने और व्यय करने के निर्णयों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होने में सहायता करता है। यह एक वित्तीय योजना प्रदान करता है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करता है और वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की दृष्टि और आकांक्षाओं के आधार पर खर्च और संसाधन आवंटन का मार्गदर्शन करता है।

मुझे ऐसे समय में बजट सत्र को संबोधित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है जब भारत एक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वृद्धि और विकास के मार्गदर्शक के रूप में सात बुनियादी सिद्धांतों- अर्थात समावेशी विकास, अंतिम जन तक पहुँच, बुनियादी विकास ढांचा, रोजगार सृजन, नवाचार, हरित विकास और वित्तीय स्थिरता पर विचार किया गया है। भारत को त्वरित आर्थिक विकास के पथ पर ले जाने के लिए 2025-26 तक राजकोषीय समेकन के परिभाषित रोड मैप के साथ-साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो व्यापक और समावेशी दोनों है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान बजट को सप्तऋषि या सूरज का सातवां घोड़ा कहा है।

जैसे कि हम अपने राज्य के लिए बजट सत्र शुरू करते हैं, हम अपने राज्य और राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद को स्वीकार करते हैं। हालाँकि, हम अपने लोगों की अपार क्षमता और लचीलेपन को भी पहचानते हैं, और एक समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।

मेरी सरकार, इस बजट के माध्यम से नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के लिए एक विकासात्मक योजना तैयार करेगी, जो केंद्रीय बजट 2023-24 के विजन के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। नया बजट राज्य और लोगों के लिए सरकार की समग्र आकांक्षाओं को प्राप्त करने में 2022-23 के बजट द्वारा तैयार किए गए विजन के निर्माण में सहायता करेगा।

2019 से, मेरी सरकार का ध्यान राज्य और इसके लोगों के समग्र विकास पर रहा है। इसके लिए, विभिन्न उपाय और कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनमें आवास, सड़क संपर्क, बुनियादी ढांचा विकास, बेहतर जल आपूर्ति, मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यापक शिक्षा प्रणाली शामिल हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व में तथा 2022-23 के बजट का हिस्सा रहीं नीतियां, जैसे कि दुग्ध उत्पादक संबंधी किसानों को दूध उत्पादन प्रोत्साहन- मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना, सुअर उत्पादन प्रोत्साहन योजना, आमा योजना और कई अन्य योजनाओं को वहन किया है। समृद्ध लाभांश और राज्य को विकास के पथ पर ले जाने की दिशा में बजटीय आवंटन के महत्व को और अधिक मजबूत किया है।

माननीय सदस्यगण,

हमारी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मेरी सरकार सिक्किम के दूर-दराज के गांवों तक के सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देना चाहती है।

इस लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए, मेरी सरकार मील का पत्थर साबित हुई है, जैसे - एस.टी.एन.एम. अस्पताल, सोचाकगैंग में पहली वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी (वीआरडीएल) की स्थापना; जिला अस्पताल नामची, जिला अस्पताल ग्यालशिंग (गेजिंग) और नए एस.टी.एन.एम. अस्पताल में कार्यात्मक हेमोडायलिसिस सेवाओं की स्थापना; एस.टी.एन.एम. में पेरिटोनियल डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं, सभी एस.एच.सी.-एचडब्ल्यूसी को जिला अस्पतालों और एस.टी.एन.एम. अस्पताल से जोड़ने वाली टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा सभी जिलों में साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर विशेषज्ञ परामर्श 102 एवं 108 शुभारंभ के साथ शुरु किया गया है।

आज, सिक्किम में 1 मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, 4 जिला अस्पताल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 148 प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 ट्रॉमा केयर सेंटर, 1 संक्रामक रोग/कोविड अस्पताल और 6 ब्लड बैंक हैं। साथ ही नवनिर्मित मंगन जिला चिकित्सालय को अतिशीघ्र कार्य संपन्न कर संचालित किया जायेगा।

हमारे राज्य के कई स्वास्थ्य सूचकों में जो सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वे मेरी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संकेत हैं। पूरे देश में 6.0 की तुलना में सिक्किम में अशोधित मृत्यु दर 4.1 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बाल लिंग अनुपात देश में 918 की तुलना में 957 है। सिक्किम में संस्थागत प्रसव 78.9% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 94.7% पर काफी अच्छा है।

हालांकि, हमारे राज्य में एक गंभीर जनसांख्यिकीय संकट की पहचान की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एन.एफ.एच.एस.) के आंकड़ों के अनुसार, सिक्किम में कुल प्रजनन दर 1.1 है जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यह 2005-06 में 3.1 की कुल प्रजनन दर से गिरावट में है।

सिक्किम में प्रजनन दर में गिरावट का राज्य के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इस मामले को मेरी सरकार ने बहुत गंभीरता से देखा है। इस गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल उपाय के रूप में, मेरी सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. सभी कामकाजी महिला कर्मचारियों (परिवीक्षाधीन शिक्षकों सहित नियमित और अस्थायी) के लिए मातृत्व अवकाश की पात्रता को 180 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया गया है। सभी पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश भी उनकी पत्नी के प्रसूति की तारीख से 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है।

2. सरकारी कर्मचारी के दूसरे बच्चे के लिए एक वेतन वृद्धि और तीसरे बच्चे के लिए दो वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आम जनता के लिए, कर्मचारियों के अलावा, नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

3. इसके अलावा, 'वात्सल्य' योजना के तहत, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ.) उपचार से गुजरने वालों को 3 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में राज्य के सरकारी कर्मचारी और गैर-कर्मचारी दोनों शामिल होंगे।

इनके अलावा, मेरी सरकार ने हाल ही में मोबाइल विलेज क्लीनिक भी शुरु किए हैं। वर्तमान में, ऐसे 8 क्लीनिक हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक मेडिकल डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन और ड्राइवर हैं। यह कार्यक्रम जनता को उनके द्वार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के उत्थान के लिए चलाया जा रहा है।

इन क्लीनिकों द्वारा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे संचारी रोगों और गैर-संचारी रोगों सहित रोगियों की जांच, बुनियादी निदान, मुफ्त दवाओं का वितरण और पी.एच.सी. या जिला अस्पतालों को रेफर करने जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रसव पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण, स्तनपान आदि सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के अपने प्रयास में मेरी सरकार द्वारा बहुत कुछ किया गया है। यद्यपि हमने इतने कम समय में अभूतपूर्व प्रगति की है, सिक्किम को उत्तर पूर्व के हेल्थकेयर हब में बदलने की आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यगण,

एक अन्य क्षेत्र जिसे मेरी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, वह है शिक्षा का क्षेत्र। मेरी सरकार मानती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विकास का एक शक्तिशाली चालक है और गरीबी को कम करने के लिए सबसे मजबूत उपकरणों में से एक है जिससे लोगों के जीवन में सुधार होता है। मेरी सरकार की प्राथमिकता है कि गुणवत्तापूर्ण और व्यापक शिक्षा प्रदान करना ताकि हमारे बच्चों को आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने के लिए तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरश: लागू करने के प्रयास जारी है।

अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ई.सी.सी.ई.) पर विशेष जोर दिया गया है। सिक्किम सभी सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसे एन.ई.पी. 2020 में भी शामिल किया गया था। जहाँ तक संभव हो, आँगनवाड़ी केंद्रों को सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सह-स्थापित किया गया है। इसके अलावा, सभी प्राथमिक शिक्षकों को ई.सी.सी.ई. प्रशिक्षण द्वारा कवर किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम ने मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफ.एल.एन.) सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मेरी सरकार प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-अधिगम परिणामों में सुधार की दिशा में आगे काम कर रही है। 2022-23 में सभी 767 स्कूल प्रमुखों और 1532 प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, मेरी सरकार पहले ही 102 जूनियर हाई स्कूलों में जूनियर टिंकरिंग लैब स्थापित कर चुकी है और नए वित्तीय वर्ष में इनमें और वृद्धि करेगी।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर, हम स्कूलों की संख्या के मामले में व्यावसायिक शिक्षा में संतृप्ति प्राप्त करेंगे। अगला उद्देश्य विविधीकरण की ओर बढ़ना है, अर्थात अधिक व्यावसायिक विषयों को जोड़ना है। मेरी सरकार एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और इंजीनियरिंग) विषयों के लिए अलग प्रयोगशाला स्थापित करके हमारे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। हम छात्रों के इस्तेमाल के लिए 147 स्कूलों को 4410 टैबलेट बांटने की प्रक्रिया में हैं।

ड्रॉप आउट के मुद्दे को हल करने के लिए, जो ज्यादातर लड़कियों के बीच प्रचलित है, मेरी सरकार ने "बहिनी" योजना शुरु की है, जिसमें सरकारी स्कूलों में लगभग 20,000 लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत 134 स्कूलों को इंसीनरेटर की सुविधा दी जाएगी। इस पहल के पीछे का मकसद मासिक धर्म चक्र के आस-पास की परेशानियों को हल करना और हमारी छात्राओं को सशक्त बनाना है। मेरी सरकार शीघ्र ही राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं तक इस योजना का विस्तार करेगी।

सिक्किम ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में तेजी से प्रगति की है। हम अपने राज्य को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की राह पर हैं- मेरी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 7 नए विश्वविद्यालय शुरू किए हैं; मेरी सरकार सर्वश्रेष्ठ वैश्विक शैक्षिक मानक प्रदान करने के मूल उद्देश्य के साथ चाखुंग, सोरेंग जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है। अपनी तरह के इस अनोखे विश्वविद्यालय के निर्माण को पूरा करना मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। इसके अलावा, असम लिंग्ज़े, गंगटोक जिले में महिलाओं के लिए एक विशेष कॉलेज, 50 मुफ्त छात्रावास सीटों के साथ भी कार्य योजना में है।

इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में, मेरी सरकार द्वारा 2022-23 में 100 विद्यालय के भवनों का निर्माण पूरा किया गया। अब हम "ग्रीन स्कूल" विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसमें वर्षा जल संचयन, सौर पैनल, बायो-डिग्रेडेबल टैबलेट तथा पानी शुद्ध करने वाले यंत्र जैसे घटक होंगे।

मेरी सरकार की अन्य उल्लेखनीय पहलें हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 में एजुकेशन एक्सपोजर ट्रिप शुरू की गई है, जिसमें कॉलेज के छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा और उन्हें उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर ट्रिप पर ले जाया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में 12 शिक्षण संकायों के साथ 103 छात्रों को दिल्ली, आगरा और जयपुर भेजा गया था।

2. सरकारी फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेजों में स्टेट कोटे की सीटों में पी.डब्ल्यू.डी. उम्मीदवारों के लिए 5% सीटों का आरक्षण।

3. सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय में अब सिक्किम के छात्रों के लिए पूर्ण शुल्क वाली 30 सीटों के साथ एम.बी.बी.एस. की 50 मुफ्त सीटें आरक्षित हैं।

4. 4 नवंबर, 2022 को भारत की माननीया राष्ट्रपति महोदया द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खामदोंग के एक स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई थी उक्त कार्य लगातार प्रगति कर रहा है और समय पर पूरा हो जाएगा।

5. राज्य के सीमांत परिवारों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री योग्यता छात्रवृत्ति योजना (CMMSS) के तहत, राज्य स्तर पर योग्यता प्राप्त करने वाले 50 छात्रों को कक्षा VI में राज्य के भीतर और बाहर के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है और हमारी सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित किया जाता है। सी.एम.एम.एस.एस. को आगे स्नातक स्तर तक बढ़ाया गया है और 2019 के बाद से 382 छात्र लाभान्वित हुए हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) को 2021 से 4% समस्तरीय आरक्षण दिया गया है।

सरकार द्वारा इन हस्तक्षेपों का प्रत्यक्ष परिणाम संकेतकों में ऊपर की ओर दिखाई देता है- सिक्किम की साक्षरता दर 90.8% तक पहुंच गई है, और

पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 93% और 88% है। स्कूलों में लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियों का नामांकन है और शिक्षक-छात्र अनुपात 1:9 है। यह मेरी सरकार की हार्दिक इच्छा है कि हमारे बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिले और सिक्किम देश का शिक्षा केंद्र बने।

माननीय सदस्यगण,

राज्य के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को सबसे विश्वसनीय और 'उच्च विकास क्षेत्र' के रूप में मान्यता प्राप्त है। इससे भी बढ़कर, बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्यटन, रोजगार के विशाल सृजन का कारण है। सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र में लगभग 35,000 व्यक्ति कार्यरत हैं। जबकि इस क्षेत्र में 25,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष रुप से कार्यरत हैं, लगभग 10,000 व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर हैं। वर्ष 2022 के दौरान 16,25,573 घरेलू और 68,645 विदेशी पर्यटकों ने सिक्किम का दौरा किया। इस आकड़े से निष्कर्ष निकालते हुए, 2022 में कुल मिलाकर 17,00,000 पर्यटकों ने सिक्किम का दौरा किया। राज्य में पर्यटकों की संख्या में इस वृद्धि का श्रेय सीधे तौर पर हमारी सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय उपायों को दिया जा सकता है, जिन्होंने पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

पिछले 4 वर्षों में, हमारी सरकार ने पर्यटक रुचि के स्थानों, पर्यटन स्थलों और पर्यटन सर्किटों के साथ-साथ कई नवीन पर्यटन आधारिक संरचना का निर्माण किया है। ये संरचना प्रकृति, आकार, क्षमता और मूल्य में विविध हैं और पर्यटकों की मांग को पूरा करने और आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ढांचे के अंतर को भरने के लिए बनाई गई हैं।

आज, राज्य के पास सड़क के किनारे की सुविधाएं, पर्यटक लॉज/यात्री निवास, इको-लॉज टी.आई.सी., कैफेटेरिया, मनोरंजन पार्क, तीर्थस्थल केंद्र, पर्यटक परिसर, पर्यटक सुविधा के रूप में राज्य के सभी कोनों में बिखरे हुए अद्वितीय पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर है और इसके अलावा रिसेप्शन केंद्र, प्रकृति निर्वचनीय केंद्र, साहसिक खेल-संबंधी बुनियादी ढाँचा, ग्रामीण पर्यटन उत्पाद / होमस्टे, मनोरंजन और कायाकल्प उत्पाद, MICE केंद्र भी हैं । ये संरचना पर्यटकों को लंबी ड्राइव की एकरसता से विराम देती है, जिससे उन्हें गंतव्यों के बीच अनुकूलन और ताजगी मिलती है।

हमारी सरकार समुदाय आधारित पर्यटन के रूप में सिक्किम की विशाल अप्रयुक्त ग्रामीण पर्यटन क्षमता का उपयोग करने की भी इच्छुक है। इसके लिए मेगा होमस्टे प्रोजेक्ट शुरु किया गया है, जिसके तहत क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ लगभग 1,000 होमस्टे का निर्माण किया जाएगा। होमस्टे में तीन कमरे होंगे और हमारे राज्य के तीन जातीय समुदायों के पारंपरिक डिजाइनों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाएंगे। इसके अलावा, मेरी सरकार राज्य में प्रति पर्यटक ठहरने की औसत अवधि को 3 से 5 दिन से बढ़ाकर 6-7 दिन करना चाहती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मेरी सरकार पाक्योंग हवाई अड्डे से उड़ानों के लिंकेज के माध्यम से और राज्य के लिए चल रहे रेलवे कनेक्टिविटी को तेजी से पूरा करके भारत के महत्वपूर्ण शहरों से राज्य के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए अथक रूप से काम कर रही है। एक अन्य क्षेत्र जहां हमारे राज्य के शांत और स्वच्छ वातावरण का लाभ उठाकर और सिक्किम को एक वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देकर राज्य में उच्च स्तरीय पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देकर हमारी सरकार गति प्रदान करेगी।

माननीय सदस्य:

कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 60% अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इस प्रकार, कृषि और बागवानी क्षेत्र हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिक्किम ने अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जैविक उत्पादों के निर्यात लिंकेज के माध्यम से किसानों की आय में सुधार के उद्देश्य से ब्रांडिंग, और पर्यावरण की रक्षा के मकसद से जैविक खेती की नीति अपनाई है और 76,000 हेक्टेयर कृषि भूमि वाला देश का एकमात्र पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है जिसे जैविक प्रमाणित किया गया है।

सिक्किम देश का पहला और एकमात्र जैविक खेती वाला राज्य है, इसलिए हमारी सरकार ने राज्य में जैविक उत्पादों की मात्रा बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हमारी दृष्टि देश में जैविक उत्पादों का नंबर 1 निर्यातक बनना है। इस दृष्टिकोण के साथ, मेरी सरकार ने "मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना" लागू की है, जिसके तहत अदरक, हल्दी, बकव्हीट, सिक्किम मंदारिन, बंद गोभी, फूलगोभी, मटर, चेरी काली मिर्च, गाजर, मूली, कीवी, दाल, और बड़ी इलायची, इन 13 फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को विभिन्न निश्चित दरों पर नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

इस योजना को हमारे राज्य के किसानों ने अच्छी तरह से स्वीकार किया है और इससे उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्ष 2021-2022 के दौरान, सोरेंग जिले के तारेभीर के लगभग 110 किसानों ने गाजर की खेती की और 60 हेक्टेयर भूमि से लगभग 900 मीट्रिक

टन गाजर का उत्पादन किया। इसी तरह, मेरी सरकार द्वारा विस्तारित समर्थन के कारण, दक्षिण सिक्किम में बिकमत के किसान इस्कूस उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इनके अलावा, मेरी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के प्रगतिशील किसानों और सिक्किम विश्वविद्यालय को शामिल करके संभावित वाणिज्यिक नकदी फसल उत्पादन पर सफल परीक्षण किए हैं। राज्य भर में विभिन्न स्थानों में केसर की खेती के क्लस्टर विकसित किए गए हैं। मेरी सरकार का लक्ष्य निकट भविष्य में केसर की खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार करना है।

इसके अलावा, मेरी सरकार ने किसानों को लाभान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य में जैविक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है। यह उद्यम भारत भर में कृषि-इनपुट प्रदान करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने और विशेष रुप से सिक्किम को बढ़ावा देने के विचार के साथ बनाया गया है। संपूर्ण जैविक मूल्य श्रृंखला में किसानों को सहायता प्रदान की जाती है और उनके खेतों से जैविक उत्पादों की कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसी गतिविधियों पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

माननीय सदस्यगण,

हमारी सरकार ने किसानों को दूध और सूअर का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में **"मुख्यमंत्री पशुधन समृद्धि योजना"** शुरु की है। उत्पादन से जुड़ी दो प्रमुख प्रोत्साहन योजनाएँ- दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना (MPIS) और सुअर उत्पादन प्रोत्साहन योजना, (PPIS) इस योजना का एक हिस्सा है।

मेरी सरकार एम.पी.आई.एस. के तहत 8/- रु. प्रति किलो दूध, सिक्किम दुग्ध संघ को दूध की आपूर्ति करने वाले डेयरी किसानों को देती है। इससे दूध का उत्पादन 2007-2008 में 42,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 86,524 मीट्रिक टन हो गया है। सिक्किम के किसान अब प्रतिदिन 217 मीट्रिक टन तक दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं। हमारा राज्य अब दूध का निर्यातक है।

इसके अलावा, मेरी सरकार ने व्यक्तिगत किसानों के लिए "सर्वोच्च दुग्ध उत्पादक पुरस्कार" की शुरुआत की है, जिसमें 2 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। ग्वालों / दुग्ध उत्पादकों द्वारा किए गए योगदान को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को ग्वाला दिवस की शुरुआत की है।

इसी तरह, राज्य में सुअर पालन और सुअर प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने **सुअर उत्पादन प्रोत्साहन योजना** शुरु की है, जिसमें पात्र सुअर पालकों को 50,000/- रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में

मिलते हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में आईसीएआर-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र-रानी, गुवाहाटी के तहत असम लिंग्जे पाक्योंग में मेगा सीड परियोजना शुरु की है, जहां हैम्पशायर के 75% स्टॉक को सालाना 600 संख्या में सुअर के बच्चे पैदा करने के लिए पाला जाता है। अब तक, सिक्किम में राज्य में सुअर की आबादी में 160% की वृद्धि देखी है।

इसी तरह, मत्स्य पालकों को मछली के स्थानीय उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक उत्थान और सतत आजीविका प्रदान करने के लिए, मेरी सरकार ने **"मुख्यमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना"** (एम.एम.एम.यू.वाई.) की शुरुआत की। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को उनके तालाबों में स्टॉक करने के लिए मछली के बीज की खरीद में और मछली पकड़ने के उपकरण जैसे कैस्टनेट, रॉड और लाइन, वेइंग मशीन और मछली परिवहन बक्से की खरीद में 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने **'सिक्किम गरीब आवास योजना'** के तहत ग्रामीण आबादी के लिए 3050 घरों का निर्माण पूरा किया है। यह एक आर.सी.सी. संरचना है जिसमें फर्नीचर, अलमारी, टेलीविजन आदि का प्रावधान है और लाभार्थी को प्रदान की गई संरचना में जोड़ने का प्रावधान है। इसके अलावा, **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत 1409 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1110 का निर्माण पूरा हो चुका है।

इसी तरह, सिक्किम शहरी गरीब आवास योजना (SUGAY) के तहत, मेरी सरकार ने पहली पूरी तरह से राज्य प्रायोजित शहरी आवास योजना शुरू की है, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के अनुरुप बनाया गया है। सभी सात यू.एल.बी. में 688 वर्ग फुट के कुल 260 सामाजिक आवास फ्लैट और 678.50 वर्ग फुट के 502 व्यक्तिगत घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, एक तीन मंजिला **"बेघर परिवारों के लिए आश्रय"** जिसमें 40 निराश्रित की कुल क्षमता वाले पुरुष और महिला शयनगृह शामिल हैं, एक रसोई, भोजन, कार्यालय और एक केयरटेकर का क्वार्टर बनाया जा रहा है और गंगटोक में सोशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एकीकृत किया जा रहा है। यह निराश्रित लोगों को सम्मानित आश्रय प्रदान करेगा।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं को सही दिशा में सफलतापूर्वक लागू कर रही है।

जल जीवन मिशन के तहत, सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में सभी घरों को 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना की है, मेरी सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद 2020-21 के दौरान 112 एनआरडीडब्ल्यूपी योजनाओं को पूरा किया है। सिक्किम में मिशन के शुभारंभ के बाद 38,694, परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि सिक्किम के 439 गांवों में से 156 गांवों ने 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन

(एफएचटीसी) हासिल कर लिया है। चल रहे सभी कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और मेरी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के भीतर सिक्किम के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए 100% एफएचटीसी सुनिश्चित करना चाहती है।

इसी तरह, **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** के तहत, दूर-दराज, दूरस्थ और पहले दुर्गम क्षेत्रों को अब सड़कों से जोड़ दिया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि क्षेत्र के निवासियों की दैनिक जरूरतों के लिए यांत्रिक परिवहन हर समय उपलब्ध है। सड़क संपर्क ने शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, कार्यालयों आदि सभी आवश्यक क्षेत्रों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में भी सहायता की है जिससे लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है। इन सड़कों ने होमस्टे और विलेज रिसॉर्ट्स जैसे ग्रामीण पर्यटन को पुनर्जीवित किया है और कृषि उत्पादों को बाजारों तक लाने में सहायता की है, जिससे ग्रामीण आबादी के बीच व्यापार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई), **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन** (एस.पी.एम.आर.एम.), **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सिक्किम गरीब आवास योजना** (एस.जी.ए.वाई.) आदि जैसी अन्य योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इनके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने विकासात्मक प्रक्रिया में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए कम से कम 50% आरक्षण की शुरुआत की है।

यह मेरी सरकार की हार्दिक इच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और विकासात्मक असंतुलन को ठीक किया जाए, इस प्रक्रिया का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंचना है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने राज्य में एक मजबूत और भरोसेमंद सड़क नेटवर्क विकसित करने के अपने मिशन में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमने नई सड़कों के निर्माण, पहले से मौजूद सड़कों के रखरखाव और उन्नयन, पुलों और पुलियों के निर्माण और राज्य में दूरस्थ बस्तियों/गांवों को जोड़ने के कार्य किए हैं। मेरी सरकार का यह निरंतर प्रयास रही है कि राज्य भर में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लिए हर गांव, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों, बाजार क्षेत्रों, पर्यटकों और धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाए।

हालांकि, एक पहाड़ी राज्य होने के नाते, भारी वर्षा और अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी को बाधित करती हैं। मेरी सरकार स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केंद्रीय सड़क मंत्रालय से लगातार संपर्क करती रही है और केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत मौजूदा और नई सड़कों को शामिल करने का भी प्रयास करती रही है। इससे न केवल सड़क नेटवर्क का एकमुश्त विकास सुनिश्चित होगा बल्कि इन सड़कों के बार-बार रखरखाव की समस्या का भी समाधान होगा।

अन्य उपलब्धियों में, भारत-नेपाल सीमा के साथ उत्तरे से चेवाभंजयांग सड़क तक कनेक्टिविटी हासिल की गई है। सड़क सीमा, व्यापार को मजबूत करेगी और अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेगी। रंगित नदी पर किच्चुदुमरा में नामची- सिक्की रोड पर पुल और कटेंग काली खोला, नामथांग पर पुल का काम पूरा हो गया है। मेरी सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सड़क सुरक्षा उपायों को भी अपनाया है। सरकार ने वर्ष 2022-23 में सड़कों के अलावा कुल 4466.60 लाख रुपये की राशि से नए निर्माण की मंजूरी दी है।

माननीय सदस्यगण,

IT और ITeS क्षेत्र में मेरी सरकार का ध्येय वाक्य है – "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस"। मुख्य ध्यान आईसीटी-सक्षम सर्वांगीण सतत विकास और राज्य के समावेशी विकास को लाने पर है; नागरिकों के दरवाजे पर पारदर्शी, सस्ती और कुशल सार्वजनिक सेवा प्रदान करना; और डिजिटल समावेशन के माध्यम से सभी का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। (महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर विशेष जोर)

90% से अधिक की साक्षरता दर के साथ, सिक्किम में स्थानीय स्तर पर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान स्नातक हैं और समग्र रूप से उच्च साक्षर मानव संसाधन है, जो सफल आई.टी., बैक-ऑफिस संचालन, बी.पी.ओ., ई.-कॉमर्स, का आधार हो सकते हैं । कौशल विकास और प्रशिक्षण क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सरकार नवाचार चलाने और रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा करने के मामले में विशेष ध्यान देगी।

मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2022, मार्गाधिकार नीति, ई- वेस्ट नीति और आई.टी. विक्रेता सूचीकरण नीति तैयार की है। विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाएं और अन्य आई.टी.-संबंधित परियोजनाएं, जैसे ई-जिला/सिक्किम सरकारी सेवा पोर्टल, ई-ऑफिस, स्टेट डेटा सेंटर, स्टेट पोर्टल, बेरोजगार युवा डेटाबेस, टास्क मॉनिटरिंग सिस्टम, ई-विधान आदि नागरिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता, पारदर्शिता और सुचारु वितरण सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

पाक्योंग, सिक्किम में एक अत्याधुनिक आई.टी. पार्क और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) का उद्घाटन किया गया है। यह संस्थान आई.टी. से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान करेगा जो आईटी के क्षेत्र में बेरोजगारों के कौशल को बढ़ाने में सहायता करेगा।

मेरी सरकार प्राथमिक से तृतीयक स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए निवेश करना जारी रखेगी। हम कौशल विकास कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता देंगे जो हमारे नागरिकों को आधुनिक कार्यबल में भाग लेने और आई.टी. क्षेत्र के माध्यम से हमारे राज्य के विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे।

माननीय सदस्यगण,

सिक्किम अपने प्राकृतिक संसाधनों, वनों, पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा और संरक्षण के मामले में सबसे आगे है। पिछले ढाई दशकों में वन क्षेत्र में 4 प्रतिशत की वृद्धि राज्य की पर्यावरण अनुकूल नीति का प्रमाण है।

मेरी सरकार ने हर साल 07 जुलाई को '**ए डे फॉर मदर अर्थ**' पहल शुरू की है जिसके अंतर्गत राज्य भर में सुबह 11 बजे से 11.07 बजे तक 7 मिनट के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है। '**मेरो रूख मेरो संतति**' पहल के तहत सिक्किम में पैदा होने वाले प्रत्येक शिशु के लिए 100 पेड़ लगाकर माता-पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना, पेड़ को बढ़ता हुआ देखना, जैसे-जैसे बच्चा बढ़ता है, उनके आगमन की याद दिलाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है और प्रकृति प्रति के प्रेम और सम्मान को दर्शाता है जो हमारे ग्रह के लिए भी फाइदेमंद है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, एक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के रूप में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पानी के व्यावसायिक उपयोग के लिए भुगतान हेतु एक अभिनव नीति साधन "पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान" लागू किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र सेवा नीति के लिए इस भुगतान की उत्पत्ति राज्य के सांस्कृतिक लोकाचार में निहित है जहां पर्यावरण को उच्च स्थान पर रखा गया है।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए, मेरी सरकार ने 2 लीटर तक की बोतलबंद पेयजल की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लोगों और हितधारकों से समान रूप से सकारात्मक समर्थन मिला है। मेरी सरकार ने पटाखों, स्टायरोफोम उत्पादों, कचरे को जलाने, टायरों को जलाने, पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग, सरकारी समारोहों और बैठकों और औषधीय पौधों के व्यापार में पैकेज्ड पेयजल की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध जैसी कई

पर्यावरण-अनुकूल नीतियों को भी लागू किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

इनके अलावा, शहरी वानिकी को मजबूत करने और हमारे कस्बों और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई पहलें चल रही हैं। पांच जिलों गंगटोक, सोरेंग, ग्यालशिंग (गेज़िंग), नामची और पाक्योंग के लिए "नगर वन योजना" को मंजूरी दी गई है और इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लागू किया जाएगा। ये नगर वन, नगरीय और परिनगरीय क्षेत्रों में हरितक्रांति के रूप में कार्य करेंगे।

मेरी सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण, स्थानीय समुदाय को संगठित करने और उन्हें बाजारों से जोड़ने के माध्यम से विभिन्न ईको-टूरिज्म स्थलों को और मजबूत करने की इच्छा रखती है। उच्च मूल्य वाले पर्यटन जैसे पक्षी विहार, ट्रेकिंग पर्यटन, साहसिक पर्यटन, संस्कृति पर्यटन आदि को विकसित किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा नामित विश्व धरोहर स्थल कंचनजंघा राष्ट्रीय उद्यान (के.एन.पी.) के भीतर पर्यटन बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। मेरी सरकार सेरीकल्चर और जैविक रेशम के साथ-साथ राज्य के औषधीय और सुगंधित पौधों का स्थायी रूप से व्यावसायीकरण करने पर भी विचार कर रही है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार राज्य में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में दृढ़ है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखेंगे। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेश को आकर्षित करने वाला अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में काम करेंगे।

मेरी सरकार ने पहले भी सक्रिय कदम उठाए हैं और सही प्रोत्साहन दिए हैं, जिसके कारण राज्य ने पिछले दशक में लगभग 30 फार्मा कंपनियों से करीब 500 मिलियन डॉलर का निवेश हासिल किया है। इस प्रकार, सिप्ला, सन फार्मा, ज़ाइडस कैडिला, एलेम्बिक, आई.पी.सी.ए., अल्केम लैब, इंटास फार्मा, टॉरेंट फार्मास्युटिकल्स और यूनिकेम जैसी मार्की कंपनियों के राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक प्रमुख फार्मा हब के रूप में उभर रहा है।

औद्योगिक इकाइयों के साथ व्यापार में आसानी के लिए, ऑनलाइन सहमति प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (OCMMS) स्थापित करने के लिए सहमति और संचालन करने के लिए सहमति जारी की गई है। साथ ही, अत्याधुनिक वायु और जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। साथ ही, छोटे राज्य सिक्किम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को

लुभाने के लिए केंद्र और राज्य से आकर्षक प्रोत्साहन और सब्सिडी को सही तरीके से लागू किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने एमएसएमई नीति 2021 में लागू किया है, जिसका उद्देश्य उत्पादन और सेवाओं को बढ़ाने , स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सुविधा, सेवाएं, प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना है और उन्हें राज्य और देश के बाहर अपनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने में सक्षम बनाना है। जागरूकता, संवेदीकरण और एक्सपोजर द्वारा राज्य के भीतर उद्यमिता; कौशल विकास प्रशिक्षण आदि प्रदान करके युवा उद्यमियों की सहायता करना जैसी नीति एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देगी।

आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक कुशल और उत्पादक कार्यबल आवश्यक है। बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं के बीच, कई देशों के सामने एक बड़ी चुनौती है। युवाओं का कौशल उनके आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश, उद्यमिता, अनुकूलन क्षमता, व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कौशल विकास पहलों में निवेश करना जो युवाओं के लिए सुलभ और प्रासंगिक अवसर प्रदान करता है और बड़े पैमाने पर व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकता है।

मेरी सरकार युवाओं को साबुन बनाने, मोमबत्ती बनाने, पैकेजिंग, सिलाई, कंप्यूटर अनुप्रयोगों आदि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही है । इसके अलावा, "कुशल युवा स्टार्ट-अप योजना (SYSS)" बेरोजगारी को कम करने और लंबे समय में पर्याप्त स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने की दृष्टि

से शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य सिक्किम के ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीच ऋण (श्रेणी अनुसार) प्राप्त करा के विनिर्माण, सेवा, व्यवसाय, सहकारी, कृषि और संबद्ध गतिविधियों की स्थापना करके स्वरोजगार बनने के लिए समान उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना है। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लिए सरकार से बैक एंडेड सब्सिडी सहायता 50% और 35% वित्तीय रूप से व्यवहार्य / बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत के लिए है। इसके अलावा, मेरी सरकार ने प्रशिक्षण और उद्यमिता को एकीकृत करने की भी पहल की है।

सिक्किम ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन फाउंडेशन (AIC-SMUTBI) भी स्थापित किया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला अटल इनक्यूबेशन सेंटर भी है। इनक्यूबेटर प्रौद्योगिकी और नवाचार के आधार पर प्रारंभिक चरण के उद्यमशीलता उपक्रमों की देखभाल करता है और इनक्यूबेटर युवा उद्यमियों को बुनियादी ढाँचा, सलाह और बीज अनुदान प्रदान करता है। यह युवा उद्यमियों को स्वरोजगार पैदा करने में अपने कौशल को निखारने और अद्यतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार ने राज्य में युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए लक्षित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समर्थन सुनिश्चित करने के लिए 'एक परिवार, एक उद्यमी' योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सिक्किम में निजी उद्यमों के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है, जिसमें बड़े पैमाने पर नौकरी करने वालों के बजाय नौकरी चाहने वाले शामिल हैं।

मेरी सरकार भारत और विदेशों में निवेशकों से निजी निवेश को प्रोत्साहित करने में अपनी ऊर्जा समर्पित करेगी और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से स्टार्टअप्स और उद्योगों के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

माननीय सदस्यगण,

सिक्किम में महिलाओं को सर्वाधिक आदर और सम्मान दिया जाता है। उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए, मेरी सरकार ने एक वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन की स्थापना की है, जो निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सेवा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, जिला बाल संरक्षण इकाइयों के परामर्श से 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को सहायता प्रदान की जा रही है।

सरकारी सेवा व नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण और पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, सरकारी कार्यों के लिए निविदा बोली में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है।सिक्किम की महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।

मेरी सरकार'आमा' योजना के अंतर्गत राज्य में रहने वाली पात्र गैर कामकाजी महिलाओं के बैंक खातों में 20-000/- रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिसका उपयोग चिकित्सा, शिक्षा और अन्य विविध खर्चों के लिए किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बचत की

आदतों को प्रोत्साहित करना और गैर-कामकाजी माताओं को समर्थन देना है।

माननीय सदस्यगण

मेरी सरकार हमारे नागरिकों के कल्याण विशेष रुप से हाशिए पर और कमजोर लोगों के लिए के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश करेंगे जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।

वर्तमान में, मेरी सरकार सिक्किम अविवाहित महिला पेंशन योजना के तहत 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 2,000/- रुपये प्रति माह प्रदान कर रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस प्रकार रु 500/- रुपये से दर में संशोधन, 60-69 वर्ष से कम आयु वालों के लिए 1,000/- प्रति माह से रु. 1,500/- प्रति माह, 70- 79 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1,500/- प्रति माह से रु. 2,000/, और 80 वर्ष और उससे अधिक के लिए रु 2,000/- से रु. 2,500/- प्रति माह की गई है। इस संशोधन से होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। मेरी सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये अतिरिक्त प्रदान कर रही है। 500/- प्रतिमाह जिससे पेंशन रु. 1,500/- प्रति माह से रु. 2,000/- प्रतिमाह और विधवा पेंशन की आयु 40 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत, अतिरिक्त रु. 500/- प्रति माह प्रदान किया जा रहा है जिससे 1,500/- से रु. 2,000/- रुपये प्रतिमाह की दर में

वृद्धि हुई है। मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य निःशक्तता पेंशन को भी बढ़ाकर 1,000/- से रु. 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया है।

माननीय सदस्यगण,

मैंने पिछले 4 वर्षों में अपनी सरकार की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों को उजागर करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया है। जबकि हमने जो हासिल किया है उस पर हमें गर्व है, हम मानते हैं कि अभी और काम किया जाना बाकी है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए जो हमारे नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमें अपने राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए एक उज्ज्वल, अधिक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए।

अंत में, मैं इस सम्मानित सदन के सदस्यों को हमारे राज्य के लिए हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में उनके अटूट समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बजट सत्र को संभव बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। हमारे राज्य के नागरिकों को उनके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि यह बजट हमारे राज्य के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा । मैं आप सभी से साथ मिलकर हमारी दूरगामी दृष्टि को वास्तविकता में परिणत करने के लिए सहयोग की अपेक्षा एवं आशा करता हूँ।

धन्यवाद,

मैं कामना करता हूँ कि बजट सत्र उपयोगी और फलदायी होगा।

जय हिन्द!!

जय सिक्किम!!!

सत्यमेव जयते

ADDRESS

OF

SHRI LAKSHMAN PRASAD ACHARYA

HON'BLE GOVERNOR OF SIKKIM

AT

SIKKIM LEGISLATIVE ASSEMBLY

ON

17th MAY, 2023

Honourable Speaker, distinguished members of the House,

It is my privilege to present the Governor's address, which highlights the key priorities and initiatives of our government for the upcoming fiscal year. The state budget is a crucial financial planning tool that helps the government manage its finances, implement policies, allocate resources, and be accountable to the public for its spending decisions. It provides a financial plan that outlines projected income and expenses for a specific period and guides spending and resource allocation based on the vision and aspirations of the Government for the fiscal year.

It brings me great pleasure to address the Budget session at a time when India is steering towards an Aatmanirbhar Bharat. In this Amrit Kaal, the 25-year lead up to India @ 100, the Union Budget has set its vision for India @ 100.

The Union Budget 2023-24 has considered the seven basic principles-, namely, inclusive development, last mile connectivity, infrastructure development, employment generation, innovation, green growth and financial stability as the guiding canons for growth and development. The budget has focused on macroeconomic stability together with a defined road map of fiscal consolidation until 2025-26 to steer India to the path of accelerated economic growth, which is both comprehensive and inclusive. The Reserve Bank of India has rightly called the current Budget the Sapth Rishi or the seventh horse in the chariot of the Sun.

As we commence the budget session for our State, we acknowledge the challenges faced by our state and our nation, especially during and after the Covid-19 pandemic. However, we also recognize the immense potential and resilience of our people,

and our commitment to building a prosperous and inclusive society remains unwavering.

My Government, through this Budget, will chart a developmental plan for the State for the New Fiscal Year which is well aligned with the vision of the Union Budget 2023-24. The new Budget will help in building onto the vision drawn by the budget of 2022-23 in achieving the Government's overall aspirations for the State and the people.

Since 2019, the focus of my government has been the holistic development of the State and its people. For this, various measures and programmes have been undertaken that include housing, road connectivity, infrastructure development, access to water, robust healthcare facilities, and a comprehensive education system.

I am delighted to inform you that the policies and initiatives that were part of the Budget of 2022-23, such as the Milk Production Incentive to milk producing farmers - the Mukhya Mantri Krishi Aatmanirbhar Yojana, the Pig Production Incentive Scheme, Aama Yojana, and many others have borne rich dividends and have further cemented the importance of the Budgetary allocations towards steering the State on the path of development.

Hon'ble Members,

The health sector has been accorded the topmost priority by my Government. My Government wants to foster a healthy society through the provision of quality healthcare services for all its citizens even up to the remotest villages of Sikkim.

While working towards this goal, my Government has achieved remarkable milestones, such as - the Establishment of the first Viral Research and Diagnostic Laboratory (VRDL) at STNM Hospital, Sochakgang; the setting up of Functional Hemodialysis Services in District Hospital Namchi, District Hospital Gyalshing and the New STNM Hospital; Peritoneal Dialysis services has been introduced in STNM, the launch of Tele Consultation services connecting all the SHC-HWC to the District Hospitals and STNM Hospital has been undertaken. Specialist consultation in all the districts on a weekly roster basis has been initiated by my Government along with the launch of 102 & 108 Ambulance Services (Referral Transport Services) which can be availed free of cost by all beneficiaries by calling the toll-free numbers 102 and 108.

Today, Sikkim boasts of 1 Mutli-speciality Hospital, 4 District Hospitals, 2 Community Health Centres, 24 Primary Health Centres, 148 Primary Health Sub-Centres, 2 Urban Primary Health Centres, 4 Trauma Care Centres, 1 Infectious Disease /COVID Hospital, and 6 Blood Bank Centres. Also, the newly constructed Mangan District Hospital will be made functional and operationalized very soon.

The positive changes reflected in many Health Indicators of our state are indicative of the tremendous work done by my Government. The Infant Mortality Rate (SRS 2020) in Sikkim is 5 per 1000 live births as compared to 28 per 1000 live births in the country. The Crude Death rate in Sikkim is 4.1 as compared to 6.0 for the country as a whole. The Child Sex Ratio in the age group of 0-6 years as per Census 2011 is 957 as compared to 918 in the country. The institutional delivery in Sikkim is quite good at 94.7 % as compared to the national average of 78.9 %.

However, a serious demographic crisis has been identified in our State. According to data from the National Family Health Survey-5 (NFHS), the total fertility rate in Sikkim is at 1.1 which is below the replacement level. This is a significant decline from the total fertility rate of 3.1 in 2005-06.

The decline in the fertility rate in Sikkim has serious implications for the state's demographic profile and the matter has been viewed very seriously by my Government. As an immediate measure to address this pressing issue, my Government has taken the following steps:

1. The Maternity Leave entitlement for all working women employees (regular and temporary including Probationary Teachers) has been increased from 180 days to 365 days. Paternity Leave for all male Government employees has also been increased from 15 days to 30 days from the date of confinement of his wife.

2. Benefit of one increment for the second child and two increments for the third child of a government employee shall be provided. For the general public, other than employees, cash incentives shall be provided.

3. Moreover, under the 'Vatsalya' Scheme, an amount of Rs.3 lakhs financial assistance is provided to those undergoing In-vitro Fertilization (IVF) treatment. The scheme will cover both Government employees and non-employees of the State.

In addition to these, my government has also recently introduced Mobile Village Clinics. Currently, there are 8 such clinics, each manned by a Medical Doctor, Nurse, Pharmacist, Lab Technician

and Driver. This programme is being undertaken to uplift the health facilities in remote areas by delivering quality health facilities for the public at their doorstep.

Basic health services such as examination of patients including Communicable Diseases and Non-Communicable Diseases, basic diagnostics, dispensing of free medicines and referral to PHC or District Hospitals are being provided by these Clinics. Special attention is paid to Maternal and Child Health, including antenatal care, immunization, nutrition, breastfeeding etc.

A lot has been done by my Government in its endeavour to provide universal access to equitable, affordable and quality healthcare services that are accountable and responsive to the people's needs. Though we have made phenomenal progress in such a short span, there is more that needs to be done to achieve the aspiration of turning Sikkim into the Healthcare Hub of the North East.

Hon'ble Members,

Another sector that has been accorded utmost priority by my Government is the education sector. My Government recognizes that quality education is a powerful driver of development and one of the strongest tools for reducing poverty there by improving the lives of the people. Providing quality and comprehensive education to equip our children to face and overcome the challenges of the ever-evolving modern world is a priority of my Government. Efforts are on, for the implementation of the National Education Policy 2020 in letter and spirit.

Special emphasis has been laid on Early Childhood Care and Education (ECCE). Sikkim is the first state to implement the

kindergarten system in all government schools, which was also incorporated in the NEP 2020. Wherever possible, Agawanwadi centres have been co-located in the Government Primary schools. Furthermore, all primary teachers will be covered by the ECCE training.

Among the North East States, Sikkim has topped the Foundational Literacy and Numeracy (FLN) Index 2022. My Government is further working towards improvement in teaching-learning outcomes at the primary level. In 2022-23, training of all 767 school heads and 1532 primary teachers was undertaken. Moreover, my Government has already set up Junior Tinkering Labs in 102 Junior High Schools and will be making more additions to these in the new financial year.

At the secondary and senior secondary levels, we will achieve saturation in vocational education in terms of the number of schools. The next objective is to move towards diversification, i.e., adding more vocational subjects. My Government will also be focusing on developing a scientific mind in our students by setting up separate laboratories for STEM (Science, Technology, Mathematics and Engineering) subjects. We are in the process of distributing 4410 tablets to 147 schools for use by the students.

To address the issue of school dropouts which is prevalent mostly amongst the girl students, my Government has introduced the **"Bahini"** Scheme wherein, about 20,000 girls' students in government schools will be provided with free of cost sanitary napkins. Additionally, 134 schools will be facilitated with Incinerators under this scheme. The motive behind this initiative is to eradicate the stigma around the menstrual cycle and to empower our girl students. My Government will further extend

the scheme to girl students studying in Government colleges of the State shortly.

Sikkim has taken rapid strides over the past four years in the field of Higher Education. We are on the path of developing our state as a hub for higher education- my Government has started 7 new universities in the last 4 years; my government is setting up the Netaji Subash Chandra Bose University of Excellence, at Chakhung, Soreong District, with the basic objective of providing the best global educational standards. Completion of the construction of this one-of-a-kind University is one of the main priorities. Furthermore, an exclusive college for women at Assam Lingzey, Gangtok District, with 50 free hostel seats is also in the pipeline.

In terms of infrastructure development in this sector, 100 school buildings were completed in 2022-23 by my Government. We will now move towards developing **"Green Schools"**, which will have components like rainwater harvesting, solar panel, bio-degradable tablets, and water purifier.

Other notable initiatives of my Government are:

I. Education Exposure Trips has been launched in the FY 2022-23 wherein college students will be selected on a merit basis and shall be taken on exposure trips to enhance their knowledge base. In the FY 2022-23, 103 students along with 12 teaching faculties were sent to Delhi, Agra and Jaipur.

ii. 5 % reservation of seats for PwD candidates in State quota seats in Government pharmacy and Nursing colleges.

iii. 50 free MBBS seats along with 30 full fees seats are now reserved for students from Sikkim at Sikkim Manipal University.

iv. The Foundation stone for a permanent campus of the National Institute of Technology, Khamdong was laid by the Hon'ble President of India on 4th November 2022. The said work is making steady progress and will see timely completion.

v. Under the Chief Minister's Merit Scholarship Scheme (CMMSS) for the students of marginalized families of the state, 50 students who qualify at the state level are admitted in class VI to reputed public schools within and outside the state and are fully sponsored by my Government. The CMMSS has further been Extended up to Graduation Level and 382 students have benefited since 2019. Children with Special Needs (CWSN) have been given 4 % horizontal reservation from 2021.

A direct result of these interventions by the Government is the upward movement in the indicators- Sikkim has reached a literacy rate of 90.8%, and the literacy rate for men and women stands at 93% and 88%, respectively. There are more girls enrolled in schools than boys and the teacher-pupil ratio stands at 1:9.

It is my Government's earnest desire to see that our children get the best education and that Sikkim becomes the education hub of the nation.

Hon'ble members,

Tourism is recognized as the most reliable and 'high growth sector' to foster sustainable development of the State. More so, tourism accounts for vast employment generation to redress the problems associated with unemployment. The tourism sector in Sikkim employs about 35,000 persons. While 25,000 persons are directly employed in this sector, about 10,000 persons rely on tourism for their livelihood indirectly. During the year 2022, 16,25,573 domestic and 68,645 foreign tourists visited Sikkim. Concluding from this data, altogether 17,00,000 tourists visited Sikkim in 2022. This rise in the number of tourist footfalls in the State can directly be credited to proactive measures taken by my Government which have propelled the tourism sector to greater heights.

Over the past 4 years, my Government has created numerous innovative tourism infrastructures at places of tourist interest, tourist destinations and along the tourist circuits. These infrastructures are diverse in nature, size, capacity and value and have been created to cater to the specific nature of demand of the tourists and fill the infrastructure gap wherever required.

Today, the State boasts unique tourism infrastructures scattered in all the corners of the state in the form of Wayside Amenities, Tourist Lodges/Yatri Niwas, Eco-lodges/Huts, TICs, Cafeterias, Amusement Parks, Pilgrimage centres, Tourist complexes, Tourist facilitation/ reception centres, Nature Interpretation Centres, Adventure sports-related infrastructure, Rural Tourism products/Homestays, Recreation and rejuvenation products, MICE Centres and so on. These infrastructures offer a break to the tourists from the monotony of long drives through rugged

topography, acclimatizing and refreshing them between destinations.

My Government is also keen on harnessing Sikkim's vast untapped Rural Tourism potential as community-based tourism. For this, the Mega Homestay Project under which around 1,000 homestays will be constructed with a cluster approach has been initiated. The homestays will consist of three rooms and will be constructed to highlight the traditional designs of the three ethnic communities of our State. Furthermore, my Government wants to increase the average length of stay per tourist in the state from 3 to 3.5 days to 6-7 days. To achieve this goal, my Government is working tirelessly to improve the connectivity to the State from important cities in India through the linkage of flights from Pakyong Airport and by expeditious completion of ongoing Railway connectivity to the State. Another area where my Government will provide impetus is in increasing the high-end tourist arrivals in the State by taking advantage of the serene atmosphere, peace, tranquillity and clean environment of our State and promoting Sikkim as a Wellness Destination.

Hon'ble Members:

Nearly 60% of the total rural population is dependent on the agriculture sector for their livelihood. Thus, the agriculture and horticulture sectors play a vital role in driving the economy of our State. Sikkim adopted the policy of organic farming with the motive of improving farmers income through export linkage of organic products with organic branding. to promote good health and protect the environment and became the only fully organic farming state in the country with 76,000 hect of agricultural land which has been certified organic.

With Sikkim being the first and only Organic Farming State in the country, my Government has undertaken various measures to increase the volume of organic produce in the State. Our vision is to be the number 1 exporter of organic produce in the Country. With this vision, my Government has implemented the **"Mukhya Mantri Krishi Aatmanirbhar Yojana"** under which farmers producing the following 13 crops are provided cash incentives at various fixed rates - Ginger, turmeric, buckwheat, Sikkim mandarin, cabbage, cauliflower, garden peas, cherry pepper, carrot, radish, kiwi, dal (pulses), and large cardamom. This scheme has been well accepted by the farmers of our State and has led to a significant increase in the yield.

During the year 2021-2022, around 110 farmers of Taray Bhir in Soreng District took up Carrot cultivation and produced around 900 MT of carrots from 60 hectares of land. Likewise, due to the support extended by my Government, the farmers of Bikmat in South Sikkim are now producing Chayote leading to significant increase in their income.

In addition to these, my Government has conducted successful trials on possible commercial cash crop production by involving progressive farmers of Jammu and Kashmir and Sikkim University. Clusters of saffron cultivation have been developed in various locations across the State. My Government aims to expand the area under Saffron cultivation in the near future.

Moreover, my Government has entered into a Joint Venture with Indian Farm Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) to create an Organic Value Chain across the state to benefit and incentivize farmers. This venture has been formed with the idea of providing agro-inputs and promoting Organic Farming across India in general and Sikkim to be specific. Support is extended to the

farmers throughout the Organic Value Chain and guidance on activities like harvesting, processing, packaging, and marketing of the Organic produce from their farms is provided.

Hon'ble Members,

My Government, with the object of encouraging farmers to increase production of milk and pork, launched the **"Mukhya Mantri Pashudhan Samriddhi Yojana"** in the year 2020. Two major production-linked incentive schemes- Milk Production Incentive Scheme (MPIS) and the Pig Production Incentive Scheme, (PPIS) form a part of this Yojana.

Under the MPIS, my Government is providing Rs. 8/- per kg of milk to the dairy farmers, who supply milk to Sikkim Milk Union. This has led to a phenomenal increase in the production of milk from 42,000 metric tons in 2007-2008 to 86,524 metric tons in 2021-22. Sikkim milk farmers are now producing upto 217 metric tons daily. Our State is now an exporter of milk.

Furthermore, my Government has commenced the "Highest Milk Producer Award" for individual farmers with a cash prize of Rs. 2.00 Lakh and has also initiated Gwala Day" held on 1st July each year to commemorate the contribution made by Gwalas /Milk producers.

Likewise, to encourage pig farmers and pig breeding in the State, the Government has introduced the Pig Production Incentive Scheme wherein eligible Pig Farmers get up to Rs. 50,000/- as an incentive. My Government has also initiated the Mega Seed Project (MSP) under ICAR-National Research Centre (NRC) -Rani, Guwahati at Assam Lingzay, Pakyong, where 75% of Hampshire

stock are bred to produce 600 numbers of piglets annually. So far, Sikkim has seen a 160% increase in the pig population in the State.

Similarly, to encourage fish farmers towards local production of fish and to provide economic upliftment and sustainable livelihood to fish farmers, my Government introduced the **"Mukhya Mantri Matsya Utpadan Yojana"** (MMMUY). Under this scheme, a subsidy of up to 60% is provided to fish farmers in the purchase of fish seeds for stocking their ponds and in the purchase of fishing equipment like castanet, rods and line, weighing machines and fish transportation boxes.

Hon'ble Members,

Under the **Sikkim Garib Awas Yojana,** my government has completed the construction of 3050 houses for the rural populace. The houses are an RCC structure with provision for furniture, cupboards, television etc and provision for the beneficiary to add to the structure provided. Moreover, under the **Pradhan Mantri Awas Yojana,** 1409 houses have been sanctioned, out of which, 1110 have been completed.

Likewise, under the **Sikkim Urban Garib Awas Yojana** (SUGAY), my government has launched the first fully State sponsored urban housing scheme which has been designed to be aligned with the Sustainable Development Goals. A total of 260 number of Social Housing Flats each measuring 688 sq. ft and 502 individual houses measuring 678.50 sq. ft are being constructed in all the seven ULBs. In addition, a three-storied "Shelter for Homeless Households" comprising of male and female dormitories with a total capacity of 40 inmates, a kitchen, dining, office and a caretaker's quarter is being constructed and integrated into the

Social Housing Complex at Gangtok. This shall provide dignified shelter to the destitute.

Hon'ble Members,

For the holistic development of rural areas, my Government has been successfully implementing both Central and State schemes in its right earnest.

Under the **Jal Jeevan Mission,** one of the flagship programmes of the Government of India envisioned to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connections by 2024 to all households in rural India, my Government has completed 112 Nos. of erstwhile NRDWP schemes during 2020-21 despite the difficult circumstances during the Covid-19 Pandemic. 38,694 nos. of Households have been provided Tap Connections since the launch of the Mission in Sikkim while 156 villages out of 439 villages in Sikkim have achieved 100% Functional Household Tap Connections (FHTC). All the ongoing works are heading towards completion and my Government desires to ensure 100% FHTCs to all the Rural Households in Sikkim within the financial year 2023-24.

Similarly, under the **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana,** the far-flung, remote and previously inaccessible areas have now been connected by roads thereby ensuring that mechanical transport for the daily needs of the inhabitants of the region is available at all times. Road connectivity has also helped in ensuring easy access to all the essential sectors such as education, tourism, health, agriculture, offices, etc thereby raising the living standards of the people. These all-weather roads have revived village tourism like homestays and village resorts and helped

bring agricultural produce to the markets, thereby paving the way for business opportunities among the rural populace.

Other schemes such as the **Saansad Adarsh Gram Yojana** (SAGY), **Shyama Prashad Mukherjee Rurban Mission** (SPMRM), **Pradhan Mantri Awaas Yojana–Gramin, Sikkim Garib Aawas Yojana** (SGAY) etc are being implemented at its right earnest and have been instrumental in the overall development of the rural areas of the State.

In addition to these, my government has, with the view to ensure that women get adequate representation in the developmental process, introduced a 50% reservation of Women in the Panchayat Elections.

It is my Government's earnest desire to improve the quality of life in rural areas and to correct the developmental imbalances, aiming in the process, to reach out to the most disadvantaged sections of society.

Hon'ble Members,

My Government has made remarkable progress in its mission to develop a robust and dependable road network in the State. We have undertaken the works for the construction of new roads, maintenance and upgradation of already existing roads, construction of bridges and culverts and connecting remote habitations/ villages in the State. It has been a constant endeavour of my Government to expand its road network throughout the State targeting connectivity in every village, institutions of education and health, market areas, tourists and religious destinations.

However, being a hilly state, there are challenges faced in terms of heavy rainfall and unforeseen natural calamities which disrupt connectivity at large. My government has been constantly approaching the central Road Ministry for the declaration of the State Highways to National Highways and has also been trying to include the existing and new roads under the Bharatmala Scheme of the Central Government. The same will not only ensure the one-time development of the road network but will also solve the problem of the recurrent maintenance of these roads.

Amongst other achievements, connectivity from Uttarey to Chewabhanjyang road along Indo-Nepal Border has been achieved. The road will strengthen border trade and benefit the local people on both sides of the international border. The bridge over the Rangit River at Kitchudumra along Namchi- Sikkip road and the bridge over Kateng Kali Khola, Namthang have been completed. My government has also adopted various road safety measures to ensure the safety of travellers. The Government has further sanctioned 46 numbers of new construction other than fair weather roads in the year 2022-23 for a total amount of Rs. 4466.60 lakhs.

Hon'ble Members,

The motto of my Government in the IT and ITeS sector is – Minimum Government, Maximum Governance. The prime focus is on bringing about ICT-enabled all-round sustainable development and inclusive growth of the State; providing transparent, affordable and efficient public service delivery closer to the door-step of citizens; and ensuring the socio-economic empowerment of all (with special emphasis on women, youth and the marginalized) through Digital Inclusion.

With a literacy rate of over 90%, Sikkim has access to engineering and computer science graduates locally and it has a highly literate human resource pool overall, which can be the bedrock of successful IT, back-office operations, BPOs, e-commerce, and skill development and training sectors. These are avenues that the Government will pay special attention to in terms of driving innovation and creating employment and job opportunities.

My Government has framed the Information Technology Policy, 2022, the Right of Way Policy, the E-Waste Policy and the IT vend or empanelment policy. Various e-governance projects and other IT-related projects, such as the e-district/Sikkim Government Services Portal, e-office, State Data Centre, State Portal, Unemployed Youth Database, Task Monitoring System, e-Vidhan etc., have been implemented for ensuring efficiency, transparency and smooth delivery of Government welfare schemes to the citizens.

A state-of-the-art IT Park and the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) have been inaugurated at Pakyong, Sikkim. This Institute will provide IT-related courses which will help in enhancing the skills of the unemployed in the field of IT.

My Government will further continue to invest in improving the quality and accessibility of education at all levels, from primary to tertiary. We will also prioritize skill development programmes that equip our citizens with the necessary skills to participate in the modern workforce and contribute to the growth of our state through the IT sector.

Hon'ble Members,

Sikkim is a frontrunner in terms of the protection and conservation of its natural resources, forests, environment and wildlife. An increase in forest cover by 4 per cent in the last two and half decades stands as a testimony of the eco-friendly policy of the State.

Apart from the initiative, **'A Day for Mother Earth',** observed on July 07 annually during which vehicular movement is halted for 7 minutes from 11 am to 11.07 am across the State, my Government has launched the **"Mero Rukh Mero Santati"** initiative which aims to strengthen the connection between parents, children and nature by planting 100 trees for every new child born in Sikkim. Watching the tree grow, as the baby grows, is a symbolic way of commemorating their arrival and is also beneficial for the planet.

During the year 2022-23, an innovative policy instrument "Payment for Ecosystem Services" was implemented to charge for the commercial use of water from commercial establishments as an ecosystem service. The origin of this enabling payment for ecosystem services policy lies in the cultural ethos of the state where the environment is placed on a high pedestal. It is not just the services derived from the ecosystem that plays a role in the economy of Sikkim, but the respect Sikkim and its people give to nature.

To combat climate change and to maintain a clean and healthy environment, my Government has banned packaged drinking water bottles of capacity up to 2 litres. This has received positive support from the people and stakeholders alike. My Government has also implemented several eco-friendly policies such as the ban on firecrackers, Styrofoam products, burning of waste, burning of

tyres, use of polythene carry bags, use of packaged drinking water bottles in government functions and meetings and trade of medicinal plants. Efforts are being made to discourage the usage of single-use plastic products as well.

In addition to these, several initiatives to strengthen urban forestry and improve the quality of life in our towns and cities are underway. The **"Nagar Van Yojana"** for the five districts namely Gangtok, Soreng, Gyalshing, Namchi and Pakyong has been sanctioned and will be implemented during the Financial Year 2023-24. These Nagar Vans will function as green lungs of the urban and peri-urban areas.

My Government further aspires to strengthen various ecotourism destinations by way of modern infrastructure, capacity building, organizing the local community and linking them to markets. High-value tourism such as birding, trekking tourism, adventure tourism, culture tourism and the like will be developed. The tourism infrastructure within Khangchendzonga National Park (KNP), a UNESCO-designated World Heritage Site will also be strengthened. My Government is also looking into commercializing the medicinal and aromatic plant wealth of the state in a sustainable manner along with sericulture and organic silk.

Hon'ble Members,

My Government remains steadfast in its effort to promote economic growth and development in the state. We will continue to prioritize job creation, investment promotion, and infrastructure development to boost our economy. We will work towards creating a conducive business environment that attracts both domestic and foreign investments, with a particular focus on

key sectors such as health, education, agriculture, tourism and skill development.

My Government has already taken proactive steps and put in place the right set of incentives which has led to the state attracting an investment of close to $500 million from nearly 30 pharma companies in the last decade. Thus, emerging as a major pharma hub in the North Eastern region with marquee companies like Cipla, Sun Pharma, Zydus Cadila, Alembic, IPCA, Alkem Lab, Intas Pharma, Torrent Pharmaceuticals and Unichem setting up their units in the state.

For ease of doing business with industrial units, the **Online Consent Management and Monitoring System** (OCMMS) for issuance of Consent to Establish and Consent to Operate has been put in place. Also, state-of-the-art air and water quality monitoring stations have been established. Also, attractive incentives and subsidies from the centre and the state are being rightfully implemented to lure National and International Companies to the small state of Sikkim.

My Government has implemented the MSME Policy 2021 which aims to provide facilitation, services, incentives and subsidies to promote local entrepreneurs to increase production and services and enable them to export their commodities and services outside the state and country. The policy will promote the development of entrepreneurship within the state by increasing awareness, sensitization and exposure; assist young entrepreneurs by providing skill development training, etc.

A skilled and productive workforce is essential for economic growth and competitiveness. Unemployment, particularly amongst the youth, is a significant challenge faced by many

countries. Skilling of the youth is crucial for their economic empowerment, social inclusion, entrepreneurship, adaptability, personal development, and national development. Investing in skill development initiatives that provide accessible and relevant opportunities for youth can yield significant benefits for individuals, communities, and nations at large.

My Government has been providing training to the youth in many fields such as soap making, candle making, packaging, stitching, computer applications, etc. Moreover, the **"Skilled Youth Start-Up Scheme (SYSS)"** was launched with the vision to reduce unemployment and create adequate self-employment opportunities in the long run. The scheme aims to generate equitable entrepreneurial opportunities in rural as well as urban areas of Sikkim, particularly among the educated unemployed youth to become self-employed by setting up Manufacturing, Service, Business, Co-Operative, Agriculture & Allied Activities by availing loans (category-wise) with back ended subsidy assistance from the Government @ 50% for Below Poverty Line (BPL) and @ 35% for rest on financially viable/ bankable Projects cost. Furthermore, my Government has also taken the initiative to integrate training and entrepreneurship.

Sikkim has also established a Technology Business Incubation Foundation (AIC-SMUTBI) under the Atal Innovation Mission, which is also the first Atal Incubation Centre in the Northeast Region. The incubator nurses and incubates early-stage entrepreneurial ventures based on technology and innovation by providing infrastructure, mentorship, and seed grants to promising young entrepreneurs to pursue their dreams of starting their ventures. It encourages young entrepreneurs to sharpen and update their skills in generating self-employment.

Additionally, my Government has launched the **'One Family, One Entrepreneur'** scheme to ensure support through various schemes aimed at the youth and rural populace in the State. The objective of this scheme is to encourage creativity and risk-taking for private enterprises in Sikkim's society which largely comprise of job seekers rather than the job creators.

My Government will dedicate its energy in encouraging private investment from investors in India and abroad and focus on creating the enabling ecosystem for startups and industries from manufacturing and services sectors.

Hon'ble Members,

Women in Sikkim are accorded the highest respect and reverence. To create a safe and secure environment for them, my Government has set up a One Stop Centre and 181 Women Helpline which provides service to women affected by violence in private and public spaces. In addition to this, assistance to girls below 18 years of age is being provided in consultation with District Child Protection Units.

A 33% job reservation has been provided to women in Government Service and reservations not less than 50% in Panchayat Elections. Further, reservations have been made for women in Tender Bids for Government works. Sikkimese women are marching shoulder to shoulder with their male counterparts in various spheres.

The **Aama Yojana** 2023 Scheme launched by the State Government Plan shall provide financial assistance of Rs 20000 per annum directly to the bank account of all eligible non working women in the State. This financial grant can be used for medical,

educational and other miscellaneous purposes. The scheme is aimed at encouraging saving habits and supporting non-working mothers in the State.

Hon'ble Members,

My Government is deeply committed to the welfare of our citizens, especially those who are marginalized or vulnerable. We will invest in social welfare programmes that provide essential services such as healthcare, education, and social protection.

At present, my government is providing Rs. 2,000/- per month for women in the age category of 45 years to 59 years under the Sikkim Unmarried Women Pension Scheme; has enhanced the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme by Rs. 500/- thereby revising the rate from Rs. 1,000/- pm to Rs. 1,500/- pm for those under the age group of 60-69 years, Rs. 1,500/-pm to Rs. 2,000/- for 70-79 years age group, and Rs. 2,000/- to Rs. 2,500/- pm for 80 years and above. The additional expenditure incurred from this revision is being borne from the State's exchequer.

Under the **Indira Gandhi National Widow Pension Scheme,** my Government is providing additional Rs. 500/- pm thereby enhancing the pension from Rs. 1,500/- pm to Rs. 2,000/- pm and has relaxed the Widow Pension age from 40 years to 21 years. Also, under the Indira Gandhi National Disability Pension Scheme, additional Rs. 500/- pm is being provided thereby enhancing the rate from Rs. 1,500/- to Rs. 2,000/- pm. My Government has also enhanced the Chief Minister's State Disability Pension from Rs. 1,000/- to Rs. 1,500 per month.

Hon'ble Members,

I have taken this opportunity to highlight some of the notable achievements of my Government over the past 4 years. While we are proud of what we have accomplished, we recognize that there is still more work to be done. As we move forward, we must continue to focus on the issues that matter most to our citizens. We must work tirelessly to address the challenges facing our state and to build a brighter, more prosperous future for all.

In conclusion, I would like to express my gratitude to the members of this esteemed house for their unwavering support in the pursuit of our government's vision for our state. I also want to express my sincere thanks to all those who have been involved in the budget session and have worked tirelessly to make this possible, and to the citizens of our state for their continued support and trust.

I am confident that this budget will pave the way for a brighter future for our state, and I look forward to working with all of you to make our vision a reality.

Thank you, and may the budget session be fruitful and productive.

JAI HIND!!

JAI SIKKIM!!!